



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941

No. 329]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 19 सितम्बर, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2019/33.—बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,
(I) विनियम 4 में,-

क) उप-विनियम (i) में, शब्दों “अधिकतम सीमा” के पश्चात् और शब्दों तथा चिह्नों “कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)” से पूर्व, चिह्न तथा शब्द “, कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर,” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ख) उप-विनियम (ii) निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ii) क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) के पश्चात्,-

क) कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी के जमानती ऋणों (सिक्योर्ड डैट) और गैर-जमानती ऋणों (अनसिक्योर्ड डैट) के योग का समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) से अनुपात, 2:1 से कम या उसके बराबर होगा; परंतु यह कि यदि कंपनी की पूँजी (कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) से ऋण (डैट) का अधिक अनुपात कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित किया गया हो, तो वही अभिभावी होगा; या

ख) कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों [जिनमें उन सभी समनुषंगियों (सब्स्टियरीज़) के वित्तीय विवरण शामिल नहीं किए जाएँगे, जो ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हों और आवास वित्त (हाउसिंग फाइनेंस) कंपनियाँ हों जो, यथास्थिति, भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक (नेशनल हाउसिंग बैंक) द्वारा विनियमित (रेग्युलेटेड) हों] के आधार पर, कंपनी के जमानती ऋणों (सिक्योर्ड डैट) और गैर-जमानती ऋणों (अनसिक्योर्ड डैट) के योग का समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री-रिज़र्व्स) से अनुपात, 2:1 से कम या उसके बराबर होगा; परंतु यह कि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब ऐसी सभी समनुषंगियों (सब्स्टियरीज़), जो उपरोक्तानुसार शामिल नहीं की जाएँगी, के जमानती ऋणों (सिक्योर्ड डैट) और गैर-जमानती ऋणों (अनसिक्योर्ड डैट) के योग का समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री-रिज़र्व्स) से अनुपात, एकल आधार पर, 6:1 से अधिक का न हो।”

ग) उप-विनियम (iv) में, परंतुक निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि खुले बाजार (ओपन मार्केट) से किया जाने वाला बाय-बैक, कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री-रिज़र्व्स) के पंद्रह प्रतिशत से कम होगा।”

(II) विनियम 5 में, उप-विनियम (i) में, खंड (ख) में, परंतुक में, शब्दों तथा चिह्न “बाय-बैक” के पश्चात् और शब्दों “कंपनी की कुल समादत्त इक्विटी पूँजी” से पूर्व चिह्न तथा शब्द “, कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर,” अंतःस्थापित किए जाएँगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./216/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जीएन/2018/32 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात्:
 - क) 29 जुलाई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी -एनआरओ/जीएन/2019/26, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th September, 2019

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES)
(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

No. SEBI/LAD-NRD/GN/2019/33.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11 and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2019.
2. These regulations shall come into force on the thirtieth date day from of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018,-

I. In regulation 4, -

- a. in sub-regulation (i), after the word “company” and before the symbol “:”, the words and symbol “, based on both standalone and consolidated financial statements of the company” shall be inserted;
- b. sub-regulation (ii) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-:

“(ii) The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the company to the paid-up capital and free reserves after buy-back shall,-:

- a) be less than or equal to 2:1, based on both standalone and consolidated financial statements of the company:

Provided that if a higher ratio of the debt to capital and free reserves for the company has been notified under the Companies Act, 2013, the same shall prevail; or

- b) be less than or equal to 2:1, based on both standalone and consolidated financial statements of the company, after excluding financial statements of all subsidiaries that are non-banking financial companies and housing finance companies regulated by Reserve Bank of India or National Housing Bank, as the case may be:

Provided that buy-back of securities shall be permitted only if all such excluded subsidiaries have their ratio of aggregate of secured and unsecured debts to the paid-up capital and free reserves of not more than 56:1 on standalone basis.”

- c. in sub-regulation (iv), the proviso shall be replaced substituted with the following proviso, namely,-:

“Provided that the buyback from open market shall be less than fifteen per cent of the paid up capital and free reserves of the company, based on both standalone and consolidated financial statements of the company.”

- II. In regulation 5, in sub-regulation (i), in clause (b), in the proviso, after the word “company” and before the symbol “;”, the words and symbol “, based on both standalone and consolidated financial statements of the company” shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./216/19]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/32.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - a) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back Of Securities) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/26.